

15 फरवरी 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

1. 'सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी से आय और मांग बढ़ सकती है':

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

सामाजिक न्याय:

1. एक ऐसी योजना जिसने अस्पतालों का आर्थिक स्वास्थ्य खराब कर रखा है:

अर्थव्यवस्था:

1. खेती के मसले पर सहमति:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. वैज्ञानिक 'जीवित जीवाश्म' के लिए और अधिक सुरक्षा चाहते हैं:
2. केरल हाउस ने केंद्र सरकार से मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया:
3. केंद्र ने पंजाब में इंटरनेट पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश काल के कानून का इस्तेमाल किया:
4. फ्री मूवमेंट रिजीम/मुक्त आवाजाही बंदोबस्त को वापस लेने के कदम पर पुनर्विचार करें:
5. प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया:
6. क्या COVID-19 टीकों को बार-बार अपडेट करने से कोई लाभ होता है?

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

'सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी से आय और मांग बढ़ सकती है':

अर्थव्यवस्था:

विषय: कृषि, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

मुख्य परीक्षा: कृषि मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे, कृषि नीति से संबंधित मुद्दे।

विवरण:

- सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price (MSP)) की गारंटी देना कृषि नीति हलकों में महत्वपूर्ण बहस का विषय बनकर उभरा है।
- इस कदम का उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना और उपभोग मांग को प्रोत्साहित करना है, जिससे कृषि क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

एमएसपी गारंटी का विश्लेषण:

- हाल ही में क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स द्वारा ऐसी गारंटी की "वास्तविक लागत" का अनुमान लगाने और भारत के कृषि परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विश्लेषण किया गया है।
- क्रिसिल का विश्लेषण धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों सहित 16 फसलों पर केंद्रित है, जो सामूहिक रूप से भारत के कृषि उत्पादन का 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- निष्कर्ष बताते हैं कि सभी फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए विपणन वर्ष (MY) 2023 के लिए कार्यशील पूंजी में लगभग ₹ 6 लाख करोड़ के पर्याप्त निवेश की आवश्यकता हो सकती है।
- यह अनुमान कृषि क्षेत्र में ऐसी नीति को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

लागत संबंधी विचार:

- एमएसपी की गारंटी की "वास्तविक लागत" इस नीति पहल की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- मई 2023 में, जहां 16 फसलों में से आधी फसलों का कारोबार एमएसपी से ऊपर और आधी फसलों का कारोबार एमएसपी की कीमत से नीचे हुआ, क्रिसिल ने कुल लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया।
- हालांकि, मंडी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकार की खरीद रणनीतियों के आधार पर वास्तविक व्यय भिन्न हो सकता है।

किसानों और फसल विविधीकरण पर प्रभाव:

- किसानों के लिए, एमएसपी गारंटी मूल्य अस्थिरता की अवधि के दौरान स्थिर आय का वादा करती है।
- यह उन्हें धान और गेहूं जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों से परे अपनी फसल विकल्पों में विविधता लाने का आत्मविश्वास प्रदान करता है।
- सरसों और अन्य वस्तुओं जैसी फसलों में सीमित खरीद के बावजूद, एक सार्वभौमिक एमएसपी गारंटी किसानों को वैकल्पिक खेती के विकल्प तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

चुनौतियाँ और अवसर:

- हालाँकि सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की संभावना आय वृद्धि और कृषि विविधीकरण के अवसर प्रस्तुत करती है, लेकिन यह कई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है।
- नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक मुद्दों और बजटीय बाधाओं सहित कार्यान्वयन जटिलताओं को सावधानीपूर्वक संबोधित करने की आवश्यकता है।

भावी कदम:

- सार्वभौमिक एमएसपी गारंटी का कार्यान्वयन भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार और लाखों किसानों की आजीविका का समर्थन करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।
- चूंकि नीति निर्माता आगे के रास्ते पर विचार-विमर्श करते हैं, इसलिए किसानों की जरूरतों को पूरा करने, कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है।

सारांश:

- सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने का उद्देश्य कृषि आय को स्थिर करना और मांग को बढ़ावा देना है। संभावित लाभों के बावजूद, कार्यान्वयन और फसल विविधीकरण में चुनौतियाँ नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण विचार बनी हुई हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

एक ऐसी योजना जिसने अस्पतालों का आर्थिक स्वास्थ्य खराब कर रखा है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: केरल में स्वास्थ्य बीमा का वित्तीय बोझ।

विवरण:

- केरल में करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (Karunya Arogya Suraksha Padhati (KASP)) प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद, निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों पर वित्तीय दबाव पैदा कर रही है।
- सरकार पर योजना के तहत प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों पर ₹ 1,128.69 करोड़ की भारी राशि बकाया है।
- इस वित्तीय बोझ के कारण सार्वजनिक अस्पतालों में दवाओं और प्रत्यारोपण जैसी आवश्यक आपूर्ति की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को दवाओं के लिए निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना पर प्रभाव:

- सार्वजनिक अस्पताल, जो पहले स्थानीय खरीद के माध्यम से आपात स्थिति का प्रबंधन करने में सक्षम थे, अब वित्तीय संकट और सरकार से लंबित प्रतिपूर्ति के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।
- अस्पतालों को आवश्यक आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रोगी देखभाल और विकास गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।
- अस्पतालों के अधीक्षक असहायता व्यक्त करते हैं क्योंकि रोगियों को निजी स्रोतों से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर दबाव और बढ़ जाता है।

आउट-ऑफ-पॉकेट में वृद्धि (Out-of-Pocket Expenditure (OOPE)):

- आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर से आशय ऐसे खर्च से है जिसे सीधे एक रोगी द्वारा वहन किया जाता है और जहाँ बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी लागत को कवर नहीं करता है। इनमें परिवारों द्वारा सीधे वहन किये गए लागत-साझाकरण, स्व-उपचार और अन्य प्रकार के खर्च शामिल हैं।

- स्वास्थ्य पर उच्च प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च के बावजूद, केरल में प्रति व्यक्ति आउट-ऑफ-पॉकेट (OOPE/जेब की क्षमता से अधिक खर्च) देश में सबसे अधिक है, जो ₹ 7,206 तक पहुंच गया है।
- केएएसपी का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल व्यय के बोझ को कम करना था, लेकिन प्रशासनिक अक्षमताओं और विलंबित प्रतिपूर्ति के कारण इसने अनजाने में ओओपीई को बढ़ाने में योगदान दिया है।
- योजना को चलाने में उचित वित्तीय निरीक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण लागत में काफी वृद्धि हुई है और दावे लंबित हो गए हैं, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ([Comptroller and Auditor General's](#)) की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया गया है।

संक्रमण चुनौतियाँ और अस्थिरता:

- केरल में 2020 में केएएसपी को बीमा मोड से ट्रस्ट/आश्वासन मोड में बदलने से महत्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिससे दावों के खर्च में वृद्धि हुई है।
- राज्य के उच्च रुग्णता बोझ और मजबूत स्वास्थ्य-चाहने वाले व्यवहार ने योजना की वित्तीय स्थिरता को और अधिक प्रभावित किया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया निश्चित प्रीमियम स्वास्थ्य सेवा वितरण अंतर-राज्यीय अंतर को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जिससे योजना प्रशासन (व्यवस्था) में केरल का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
- आलोचनाओं के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्दा स्वयं केएएसपी के साथ नहीं है, बल्कि उस गैर-पेशेवर तरीके से है जिसमें राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) योजना का प्रबंधन करती है।
- मजबूत दावों की निगरानी का अभाव, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय अनुशासन की कमी ने केएएसपी को उसके मौजूदा स्वरूप में अस्थिर बना दिया है, जिससे सार्वजनिक अस्पतालों की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ गई है।

सारांश:

- केरल में करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP), जिसे शुरू में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के लिए सराहा गया था, अब प्रशासनिक अक्षमताओं और विलंबित प्रतिपूर्ति के कारण राज्य के वित्त पर बोझ डालती है और सार्वजनिक अस्पतालों पर दबाव डालती है, जिससे इसकी अस्थिर प्रकृति का पता चलता है।

खेती के मसले पर सहमति:**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:****अर्थव्यवस्था:****विषय: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे।****मुख्य परीक्षा: वर्तमान में चल रहा किसान आंदोलन और उनकी मांग।****प्रसंग:**

- पंजाब के हजारों किसान विभिन्न रियायतों की मांग को लेकर हरियाणा के सीमा बिंदुओं (border points) पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (border points-वह स्थान जहाँ लोग एक देश या राज्य से दूसरे देश/राज्य में जा सकें।)
- मांगों में कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कर्ज माफी, कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौतों को रद्द करना और किसानों के लिए न्यूनतम पेंशन शामिल है।
- विरोध का नेतृत्व SKM (गैर-राजनीतिक) द्वारा किया जाता है, जो पहले के विरोध से अलग एक समूह है, जो कई राज्यों में हित समूहों के भीतर आंतरिक विभाजन का संकेत देता है।

सभी क्षेत्रों में विरोध का विस्तार:

- किसानों का यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है; बल्कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा के सोनीपत और अन्य इलाकों में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर श्रम मुद्दों तक की शिकायतें शामिल हैं, जो देश भर में किसानों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों को दर्शाती हैं।
- चार श्रम संहिताओं ([labour codes](#)) को निरस्त करने सहित अतिरिक्त मांगों के साथ मूल एसकेएम और ट्रेड यूनियनों द्वारा 16 फरवरी को राष्ट्रीय ग्रामीण और औद्योगिक हड़ताल की योजना बनाई गई है।

सरकारी प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ:

- सरकार पंजाब के किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन एमएसपी की गारंटी संभव नहीं दिख रही है।
- हरियाणा और दिल्ली में पुलिस का हस्तक्षेप किसानों को राजधानी तक पहुंचने से रोक रहा है, जो 2021-22 की घेराबंदी की याद दिलाता है।
- एफसीआई (FCI) द्वारा एमएसपी-आधारित खरीद खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन असमान भौगोलिक विस्तार और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण सुधार की आवश्यकता है।
- राजनीतिक निहितार्थों पर गौर किया गया, खासकर लोकसभा चुनावों के नजदीक होने पर।

सुधार और सार्वजनिक सहमति की आवश्यकता:

- कृषि के लिए सार्वजनिक समर्थन को पुनर्जीवित करने के लिए राजनीतिक सहमति और बातचीत की तत्काल आवश्यकता है।
- मौजूदा समर्थन प्रणालियों के लाभार्थियों के बीच उत्पादन के विविधीकरण और बढ़ी हुई उत्पादकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व को देखते हुए, कृषि क्षेत्र के लिए सार्वजनिक समर्थन के एक नए मॉडल को बढ़ावा देने में सरकार की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है।

सारांश:

- भारत में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन एमएसपी, ऋण और नीति सुधारों के संबंध में शिकायतों को उजागर करते हैं। कृषक समुदाय के भीतर विभाजन और सरकार की प्रतिक्रिया एक संशोधित कृषि सहायता प्रणाली और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रिलिम्स तथ्य:**1. वैज्ञानिक 'जीवित जीवाश्म' के लिए और अधिक सुरक्षा चाहते हैं:****प्रसंग:**

- कुछ पर्यावरण समूह अमेरिकी सरकार को एक याचिका के माध्यम से "जीवित जीवाश्म" मानी जाने वाली प्रजाति अमेरिकी हॉर्सशू केकड़े के संरक्षण की वकालत कर रहे हैं।

मुद्दा:

- एक समय मध्य-अटलांटिक और खाड़ी तटों पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हॉर्सशू केकड़े की आबादी वाणिज्यिक फसल, निवास स्थान की हानि और जलवायु परिवर्तन के कारण कम हो गई है।
- इनकी संख्या में गिरावट का रूफ़ा रेड नॉट पक्षी सहित अन्य समुद्री प्रजातियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- 23 संरक्षण संगठनों द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) से हॉर्सशू केकड़े को लुप्तप्राय प्रजाति का दर्जा देने का आग्रह किया गया है।
- यह पदनाम विशेष परमिट के बिना प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने या मारने पर रोक लगाएगा और महत्वपूर्ण प्रजनन आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारक जैसे समुद्र तट का विकास और समुद्र के स्तर में वृद्धि उनके अस्तित्व को और अधिक खतरे में डालती है।

महत्व:

- इन प्राचीन प्राणियों की सुरक्षा और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए तत्काल संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।

2. केरल हाउस ने केंद्र सरकार से मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया:**प्रसंग:**

- केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) में संशोधन करने का आग्रह किया है।

मुद्दा:

- वन मंत्री ने विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 118 के तहत यह प्रस्ताव चर्चा के लिए पेश किया।
- सभी दलों के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य मानव आवासों में वन्यजीवों की घुसपैठ, फसल विनाश और पशुधन पर हमलों से निपटना है।
- सरकार ने वन्यजीव अतिक्रमण और निवासियों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण समकालीन संशोधनों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

महत्व:

- प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षकों को मानव जीवन के लिए आसन्न खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों के खिलाफ घातक बल का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, यह केंद्र सरकार से वन्यजीव आबादी नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों को लागू करने का आग्रह करता है।

3. केंद्र ने पंजाब में इंटरनेट पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश काल के कानून का इस्तेमाल किया:

प्रसंग:

- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पंजाब के चुनिंदा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन ने स्वतंत्र भाषण और सरकारी अधिकार पर चिंताओं और बहस को जन्म दिया है।

मुद्दा:

- ब्रिटिश-युग के कानून के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकार ने इस कदम के लिए सार्वजनिक आपातकाल और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, जो उन मानदंडों से अलग है जहां ऐसे निर्णय आम तौर पर राज्य सरकारों के पास होते हैं।
- दिल्ली के लिए एक नियोजित विरोध मार्च से पहले लगाया गया निलंबन, डिजिटल अधिकारों और शासन की विकसित गतिशीलता को रेखांकित करता है।
- आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं, जबकि समर्थक सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के लिए तर्क देते हैं।

महत्व:

- यह एपिसोड डिजिटल युग में सुरक्षा चिंताओं और नागरिक स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है।
- जैसे-जैसे तकनीक दैनिक जीवन के साथ तेजी से जुड़ती जा रही है, इंटरनेट पहुंच, सेंसरशिप और संचार चैनलों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़े सवाल लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चर्चा को उकसाते रहते हैं।

4. फ्री मूवमेंट रिजीम/मुक्त आवाजाही बंदोबस्त को वापस लेने के कदम पर पुनर्विचार करें:

प्रसंग:

- मिजोरम में पांच गैर-सरकारी निकायों के एक समूह ने भारत सरकार से 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को खत्म करने के अपने कदम पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

मुद्दा:

- एफएमआर ने सीमावर्ती निवासियों को वीज़ा की आवश्यकता के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति दी है।
- हाल ही में म्यांमार में गृह युद्ध और मणिपुर में जातीय संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के कारण एफएमआर को रद्द करने की घोषणा की गई थी।
- एनजीओ समन्वय समिति ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है।
- उन्होंने एफएमआर को खत्म करने और इसके बजाय सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, और सीमा के दोनों किनारों पर रहने वाले जो जातीय समूह के बीच जातीय और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

5. प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर के मंदिर का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

सम्बन्धित जानकारी:

- बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित, यह मंदिर साझा मानवीय विरासत का प्रतीक है और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

- मोदी ने भारतीय और वैश्विक दोनों समुदायों पर इसके प्रभाव पर जोर देते हुए, मंदिर को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान का आभार व्यक्त किया।
- इस कार्यक्रम में यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जो सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- इस अवसर पर मोदी ने प्रतिष्ठित संयुक्त अरब अमीरात के स्थलों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला साथ ही साथ हाल ही में अयोध्या में हुए राम मंदिर अभिषेक पर अपने विचार प्रदर्शित करते हुए, बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर का जश्न मनाया।

महत्व:

- मंदिर का उद्घाटन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करता है।

6. क्या COVID-19 टीकों को बार-बार अपडेट करने से कोई लाभ होता है?

प्रसंग:

- शोधकर्ता नियमित रूप से इन्फ्लूएंजा टीकों को परिसंचारी उपभेदों के साथ संरेखित करने के लिए अद्यतन करते हैं, फिर भी लंबी विकास प्रक्रिया के कारण एक आदर्श मिलान प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण रहता है।

मुद्दा:

- इन्फ्लूएंजा वैक्सीन की प्रभावशीलता तनाव अनुकूलता पर निर्भर करती है, जो प्रभावकारिता को 25% तक प्रभावित करती है।

- इसके अतिरिक्त, समय के साथ वैक्सीन कवरेज कम हो जाता है, जो कि COVID-19 टीकों के साथ देखी गई चुनौतियों को दर्शाता है।
- ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant), अपनी एंटीजेनिक दूरी के साथ, वैक्सीन की प्रभावकारिता को और अधिक जटिल बना देता है।
- टीकों को अद्यतन करने के प्रयासों के बावजूद, XBB.1.5 और JN.1 जैसे नए वैरिएंट बाधाएँ पेश करते हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि टीकों को अद्यतन करने से भविष्य के वैरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी टाइटर्स को निष्क्रिय करने में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभावकारिता और टी-सेल प्रतिरक्षा के बारे में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। (एंटीबॉडी टाइटर्स/antibody titers-एक प्रयोगशाला परीक्षण है जो रक्त के नमूने में एंटीबॉडी के स्तर को मापता है। रक्त में एंटीबॉडी का स्तर शरीर के पिछले अनुभव या एक एंटीजन के संपर्क में आने का प्रतिबिंब है, या कुछ ऐसा जिसे शरीर स्वयं के रूप में नहीं पहचानता है।)
- भारत, अपने कॉर्बेवैक्स और जेम्कोवैक टीकों के साथ, उभरते वैरिएंट का मुकाबला करने के लिए फॉर्मूलेशन को अपडेट करने के फैसले का सामना कर रहा है।

महत्व:

- अद्यतन बूस्टर की आवश्यकता जनसंख्या की संवेदनशीलता और उभरते SARS-CoV-2 परिदृश्य पर निर्भर करती है, जो वैक्सीन रणनीति अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण विचारों को प्रेरित करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. सीएसीपी ए2+एफएल फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की सिफारिश करती है और सरकार अंततः इसकी घोषणा करती है। यहाँ A2+FL का तात्पर्य है?

- (a) भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।
- (b) सिर्फ किसानों की लागत।
- (c) भुगतान की गई लागत प्लस पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य प्लस स्वामित्व वाली भूमि का किराये का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: a

व्याख्या:

- A2+FL का तात्पर्य भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य से है। इस सूत्र का उपयोग भारत में कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गणना के लिए किया जाता है।

प्रश्न 2. INSAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. INSAT प्रणाली, अगस्त 1983 में INSAT-1B के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई (अप्रैल 1982 में पहले असफल INSAT-1A लॉन्च के बाद)।
2. इस प्रणाली ने दूरदराज के क्षेत्रों और अपतटीय द्वीपों में टीवी और आधुनिक दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विस्तार की सुविधा प्रदान की।
3. इन्सैट डेटा का उपयोग फसलों की निगरानी और उनके स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है।
4. इन्सैट उपग्रह संकटग्रस्त जहाजों और व्यक्तियों का पता लगाने में मदद करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: d

व्याख्या:

- यह कथन सही है कि INSAT की शुरुआत अगस्त 1983 में INSAT-1B के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। INSAT-1A को इससे पहले अप्रैल 1982 में लॉन्च किया गया था।
- इन्सैट (INSAT) ने दूरदराज के क्षेत्रों और अपतटीय द्वीपों तक टीवी और आधुनिक दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विस्तार की सुविधा प्रदान की।
- इन्सैट (INSAT) डेटा का उपयोग वास्तव में फसलों की निगरानी और उनके स्वास्थ्य का आकलन करने, कृषि गतिविधियों में योगदान देने के लिए किया जाता है।
- इन्सैट (INSAT) उपग्रह संकटग्रस्त जहाजों और व्यक्तियों का पता लगाने, खोज और बचाव कार्यों में योगदान देने में भी सहायता करते हैं। इसलिए, चारों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. फ़तेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 1569 में महान मुग़ल सम्राट अकबर ने की थी और 1571 से 1585 तक फ़तेहपुर सीकरी मुग़ल साम्राज्य की राजधानी थी।
2. फ़तेहपुर सीकरी की अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण 1586 में मुग़ल राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
3. इसे वर्ष 1996 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

- फ़तेहपुर सीकरी को वर्ष 1996 में नहीं बल्कि वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था।

प्रश्न 4. डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन 'केर्न्स समूह' (Cairns group) को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

- (a) कृषि निर्यातक देशों का समूह कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी कर रहा है।
- (b) कृषि आयातक देशों का समूह कृषि व्यापार संरक्षणवाद की पैरवी कर रहा है।
- (c) 'सबसे कम विकसित राष्ट्र' की स्थिति का विरोध करने वाले देशों का समूह।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

- केर्न्स समूह कृषि निर्यातक देशों के एक समूह को संदर्भित करता है जो कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी करता है। यह समूह व्यापार बाधाओं को कम करना और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना चाहता है।

प्रश्न 5. रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. रौलेट एक्ट 'देशद्रोह समिति' (Sedition Committee) की सिफारिशों पर आधारित था।
2. रौलेट सत्याग्रह में, गांधीजी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया।
3. साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रौलेट सत्याग्रह के साथ मेल खाते थे।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

- वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति का आकलन करने का काम सौंपा गया था। इसके विपरीत, रौलेट एक्ट के विरोध में वर्ष 1919 में रौलेट सत्याग्रह हुआ।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. कृषि कानूनों को रद्द करने के सरकार के फैसले से आप कितने सहमत हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
[जीएस-3, अर्थव्यवस्था] (How far do you agree with the government's decision to repeal the farm laws? (15 marks, 250 words) [GS-3, Economy])

प्रश्न 2. स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार को सुनिश्चित करता है लेकिन अगर इसे ठीक से लागू नहीं किया गया तो यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य को पटरी से उतार सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-2, शासन/स्वास्थ्य] (Health insurance ensures the basic right to health but if not properly implemented, it may derail the economic health of the country. Critically analyse. (10 marks, 150 words) [GS-2, Governance/Health])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)